

Original Article

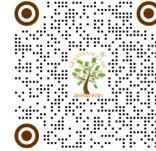
PARTY SYSTEM IN INDIAN DEMOCRACY: CHALLENGES AND PROSPECTS

भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

Vikram Das ^{1*}, Dr. Ravindra Kumar Thakur ²

¹ Research Scholar, Department of Political Science, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Bihar, India

² Department of Political Science, Lalit Narayan Janata College, Jhanjharpur, Bihar, India



ABSTRACT

English: The party system exists as a central structural element in the Indian democratic system, profoundly influencing the nation's political direction and governance processes. After independence, a multi-party system developed in India, providing political expression to diverse social, economic, and regional aspirations. The Indian National Congress clearly dominated the initial phase, but over time, the rise of regional parties and alternative political organizations has made the political landscape more multifaceted. The party system has significantly contributed to accountability by encouraging democratic participation. However, it faces numerous structural and practical challenges, including defection, political corruption, caste- and religious-based politics, and the instability of coalition governments. In contemporary Indian politics, the role of political parties is expanding beyond mere power-sharing to encompass social welfare, inclusive development, and social justice. The spread of digital technology and the active political participation of youth have infused new energy into the democratic process. This article presents a critical analysis of the historical evolution of the Indian party system, its major problems, and future prospects.

Hindi: भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में दलीय व्यवस्था एक केंद्रीय संरचनात्मक तत्व के रूप में विद्यमान है, जिसने राष्ट्र की राजनीतिक दिशा एवं शासन प्रक्रियाओं को गहन रूप से प्रभावित किया है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में बहुदलीय व्यवस्था का विकास हुआ, जिसके माध्यम से विविध सामाजिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राजनीतिक अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हुआ। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, किंतु कालांतर में क्षेत्रीय दलों तथा वैकल्पिक राजनीतिक संगठनों के उदय ने राजनीतिक परिदृश्य को अधिक बहुआयामी बना दिया। दलीय व्यवस्था ने लोकतांत्रिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए शासन को उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तथापि, इसके समक्ष अनेक संरचनात्मक एवं व्यवहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनमें दल-बदल की प्रवृत्ति, राजनीतिक भ्रष्टाचार, जाति एवं धर्म पर आधारित राजनीति तथा गठबंधन सरकारों की अस्थिरता प्रमुख हैं। समकालीन भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका केवल सत्ता-संचालन तक सीमित न रहकर सामाजिक कल्याण, समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्यों तक विस्तारित हो रही है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रसार तथा युवाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नवीन ऊर्जा का संचार किया है। यह आलेख भारतीय दलीय व्यवस्था के ऐतिहासिक विकासक्रम, प्रमुख समस्याओं तथा भावी संभावनाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

Keywords: Indian Democracy, Party System, Multi-Party System, Political Parties, Challenges, Prospects, Coalition Government, भारतीय लोकतंत्र, दलीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली, राजनीतिक दल, चुनौतियाँ, संभावनाएँ, गठबंधन सरकार

*Corresponding Author:

Email address: Vikram Das (sudhavjj@gmail.com), Dr. Ravindra Kumar Thakur (thakurravindra1970@gmail.com)

Received: 16 January 2026; Accepted: 10 February 2026; Published 24 March 2026

DOI: [10.29121/ShodhSamajikv3.i1.2026.82](https://doi.org/10.29121/ShodhSamajikv3.i1.2026.82)

Page Number: 96-100

Journal Title: ShodhSamajik: Journal of Social Studies

Journal Abbreviation: ShodhSamajik J. Soc. Stud.

Online ISSN: 3049-2319

Publisher: Granthaalayah Publications and Printers, India

Conflict of Interests: The authors declare that they have no competing interests.

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Authors' Contributions: Each author made an equal contribution to the conception and design of the study. All authors have reviewed and approved the final version of the manuscript for publication.

Transparency: The authors affirm that this manuscript presents an honest, accurate, and transparent account of the study. All essential aspects have been included, and any deviations from the original study plan have been clearly explained. The writing process strictly adhered to established ethical standards.

Copyright: © 2026 The Author(s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रभावशीलता में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत केंद्रीय मानी जाती है। ये दल नागरिकों और शासन संस्थाओं के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करते हुए जनमत के संगठन, अभिव्यक्ति तथा राजनीतिक सहभागिता को संस्थागत स्वरूप प्रदान करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल न केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम होते हैं, बल्कि वे नीति निर्माण, राजनीतिक सामाजिककरण तथा जनहित के प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया को भी सुदृढ़ करते हैं। भारत जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विविध राष्ट्र में दलीय व्यवस्था ने लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अंगीकार करते हुए बहुदलीय प्रणाली को अपनाया, जिससे विविध समूहों को राजनीतिक मंच उपलब्ध हुआ।

स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक वर्चस्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जिसके कारण इस कालखंड को प्रायः एक-दलीय प्रभुत्व की अवधि के रूप में वर्णित किया जाता है। तथापि, 1967 के पश्चात क्षेत्रीय दलों के उदय ने भारतीय राजनीति में प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप को सुदृढ़ किया। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक संरचना अधिक जटिल, बहुस्तरीय एवं प्रतिनिधिमूलक बन गई। विभिन्न सामाजिक वर्गों, जातीय समूहों, धार्मिक समुदायों तथा क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। यद्यपि दलीय व्यवस्था ने लोकतांत्रिक सहभागिता को व्यापक बनाया है, तथापि इसके साथ अनेक चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं। सत्ता केंद्रित राजनीति, वैचारिक क्षरण, दलगत अवसरवादिता तथा नैतिक मूल्यों का हास लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहा है। इस आलेख में भारतीय दलीय व्यवस्था के विकास, इसके समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों तथा भविष्य में इसके सुधार की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

भारतीय दलीय व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास

भारतीय दलीय व्यवस्था का विकास स्वतंत्रता संग्राम की प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राजनीतिक चेतना के प्रसार के साथ ही विभिन्न राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ, जिन्होंने जनसाधारण को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से हुई, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीय जनता की समस्याओं एवं मांगों को प्रस्तुत करना था। समय के साथ यह संस्था एक व्यापक जनआंदोलन में परिवर्तित हो गई और स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख राजनीतिक मंच बनकर उभरी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन जैसे व्यापक जनआंदोलनों का संचालन किया, जिसके फलस्वरूप यह एक सशक्त और प्रभावशाली राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई। [Mishra \(2017\)](#)

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अंगीकार किया तथा 1952 में प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और वह केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में सत्ता में आई। 1952 से 1967 तक के कालखंड को राजनीतिक विद्वानों ने 'कांग्रेस प्रणाली' की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि इस अवधि में कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा तथा विपक्षी दल अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में रहे। यद्यपि समाजवादी दल, जनसंघ तथा कम्युनिस्ट दल राजनीतिक परिदृश्य में विद्यमान थे, तथापि वे कांग्रेस को सत्ता से विस्थापित करने में सफल नहीं हो सके। [Verma \(2020\)](#)

1967 के आम चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी मोड़ सिद्ध हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को अनेक राज्यों में सत्ता से वंचित होना पड़ा और पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। इससे क्षेत्रीय दलों तथा गठबंधनों को नई राजनीतिक पहचान एवं सशक्तिकरण प्राप्त हुआ। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, पंजाब में अकाली दल तथा पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा जैसे दलों का प्रभाव उल्लेखनीय रूप से बढ़ा। 1977 में आपातकाल के पश्चात जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, जिसने कांग्रेस के दीर्घकालिक वर्चस्व को प्रत्यक्ष चुनौती प्रस्तुत की। इसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी दलों तथा विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सुदृढ़ उपस्थिति स्थापित की। 1990 के दशक में मंडल राजनीति के प्रभाव तथा गठबंधन सरकारों के उदय ने भारतीय दलीय व्यवस्था को पूर्णतः बहुदलीय स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार भारतीय दलीय व्यवस्था का विकास एकदलीय प्रभुत्व से बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संरचना की ओर क्रमिक रूप से हुआ। [Singh \(2019\)](#)

बहुदलीय व्यवस्था की विशेषताएँ

भारतीय राजनीतिक प्रणाली में बहुदलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक संरचना की एक आधारभूत विशेषता के रूप में विकसित हुई है। भारत जैसे सामाजिक, भाषाई, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत विविध राष्ट्र में किसी एक राजनीतिक दल के माध्यम से समस्त वर्गों एवं हितों का प्रतिनिधित्व करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। इसी कारण स्वतंत्रता के पश्चात अनेक राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों तथा सामाजिक समूहों की आकांक्षाओं को राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रदान की। भारतीय बहुदलीय प्रणाली की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता इसकी व्यापक विविधता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय दलों के साथ-साथ सशक्त क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण उपस्थिति भी देखने को मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तथा कम्युनिस्ट दलों जैसे राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय जनता दल जैसे क्षेत्रीय दल भी राजनीतिक प्रक्रिया में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। [Sharma \(2018\)](#)

इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक वर्गों, जैसे किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक समावेशी एवं प्रतिनिधिमूलक बनी है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में निरंतर वृद्धि बहुदलीय व्यवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अनेक दलों के मध्य चुनावी प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप जनता को वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प उपलब्ध होते हैं तथा सत्ता परिवर्तन की संभावना बनी रहती है, जिससे शासन संस्थाओं पर जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहने का दबाव बना रहता है। बहुदलीय प्रणाली ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन प्रदान किया है। क्षेत्रीय दलों के सशक्त होने से राज्यों की भूमिका अधिक सुदृढ़ हुई तथा केंद्र की शक्तियों पर संतुलन स्थापित हुआ, जो संघीय ढाँचे के

सुदृढीकरण में सहायक सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त गठबंधन राजनीति के माध्यम से विभिन्न दलों को शासन में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे लोकतांत्रिक सहभागिता का विस्तार संभव हुआ। [Mishra \(2017\)](#)

यद्यपि बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र को व्यापक आधार प्रदान करती है, तथापि इससे राजनीतिक अस्थिरता की समस्या भी उत्पन्न हुई है। अनेक अवसरों पर गठबंधन सरकारों की कमजोर स्थिति के कारण नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। इसके बावजूद यह प्रणाली भारत की विविध सामाजिक संरचना के अनुकूल मानी जाती है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।

गठबंधन सरकारों का प्रभाव

भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का उदय बहुदलीय व्यवस्था के स्वाभाविक विकास का परिणाम रहा है। 1967 के पश्चात जब किसी एक राजनीतिक दल के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना कठिन होने लगा, तब विभिन्न दलों ने परस्पर सहयोग के माध्यम से सरकारों का गठन आरंभ किया। इस प्रवृत्ति को 1989 के उपरांत विशेष गति प्राप्त हुई, जब राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर गठबंधन सरकारें सत्ता में स्थापित होने लगीं। राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) जैसे गठबंधनों ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को नई दिशा प्रदान की। [Sharma \(2018\)](#)

गठबंधन सरकारों का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि छोटे तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को भी शासन प्रक्रिया में सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों के हित केंद्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होने लगे। इस प्रकार शासन व्यवस्था अधिक समावेशी बनी तथा संघीय ढाँचे को सुदृढता प्राप्त हुई। यद्यपि गठबंधन राजनीति ने लोकतांत्रिक सहभागिता के दायरे का विस्तार किया, तथापि इसके साथ प्रशासनिक अस्थिरता की समस्या भी उत्पन्न हुई। गठबंधन सहयोगियों के मध्य वैचारिक मतभेद, नीतिगत असहमति तथा सत्ता में भागीदारी को लेकर उत्पन्न विवाद अनेक अवसरों पर सरकारों के पतन का कारण बने। विशेष रूप से 1990 के दशक में केंद्र स्तर पर अल्पकालिक सरकारों का गठन इस राजनीतिक अस्थिरता का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त नीति निर्माण की प्रक्रिया भी कई बार धीमी, जटिल तथा समझौतों पर आधारित हो गई। [Mishra \(2017\)](#) इसके बावजूद गठबंधन व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में संवाद, सहमति एवं सहयोग की संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों को सामूहिक रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता ने लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संस्थागत परंपराओं को सुदृढ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलीय प्रणाली ने एक ओर जहाँ राजनीतिक सहभागिता के दायरे का विस्तार किया है, वहीं दूसरी ओर इसके समक्ष अनेक गंभीर संरचनात्मक एवं व्यवहारिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। ये समस्याएँ न केवल राजनीतिक संस्थाओं की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी क्षीण करती हैं। इनमें दल-बदल की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, जाति एवं धर्म आधारित राजनीति तथा राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।

दल-बदल भारतीय राजनीति की एक दीर्घकालिक एवं जटिल समस्या रही है। अनेक विधायक एवं सांसद व्यक्तिगत हित, सत्ता की आकांक्षा अथवा मंत्री पद की प्राप्ति के उद्देश्य से अपने राजनीतिक दल परिवर्तित कर लेते हैं। इससे न केवल जनता के जनादेश की अवहेलना होती है, बल्कि शासन की स्थिरता भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है। 1967 के पश्चात इस प्रवृत्ति में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हुई, जब अनेक राज्यों में बार-बार सरकारों का गठन एवं पतन हुआ। इस समस्या पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1985 में संविधान में 52वाँ संशोधन करते हुए दल-बदल विरोधी कानून को लागू किया गया। तथापि, राजनीतिक जोड़-तोड़ तथा कानूनी कमियाँ के माध्यम से यह प्रवृत्ति वर्तमान समय में भी निरंतर बनी हुई है। [Mishra \(2017\)](#)

राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार भारतीय दलीय व्यवस्था की एक अत्यंत गंभीर चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है। चुनावी अभियानों के संचालन हेतु भारी धनराशि की आवश्यकता के कारण अवैध चंदा, काले धन के प्रयोग तथा सत्ता के दुरुपयोग को प्रोत्साहन मिलता है। अनेक बड़े घोटालों ने राजनीतिक नेतृत्व की साख को गहरा आघात पहुँचाया है। भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप नीतिगत निर्णय अक्सर जनकल्याण के स्थान पर निजी स्वार्थों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इससे जनता का राजनीतिक संस्थाओं पर विश्वास कमजोर हुआ है तथा लोकतंत्र की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न हुआ है। [Verma \(2020\)](#)

भारतीय राजनीति में जाति एवं धर्म आधारित राजनीति एक महत्वपूर्ण और जटिल चुनौती के रूप में विकसित हुई है। अनेक राजनीतिक दल चुनावी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामाजिक पहचानों का उपयोग करते हुए वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। इसके परिणामस्वरूप समाज में विभाजन की प्रवृत्ति सुदृढ होती है तथा राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता को क्षति पहुँचती है। यद्यपि विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की अनिवार्य आवश्यकता है, किंतु जब राजनीति संकीर्ण हितों तक सीमित हो जाती है, तब यह लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रतिकूल सिद्ध होती है। [Singh \(2019\)](#)

अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्पष्ट कमी दृष्टिगोचर होती है। नेतृत्व प्रायः कुछ व्यक्तियों अथवा परिवारों तक सीमित रहता है और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सामान्य कार्यकर्ताओं की भागीदारी अत्यंत सीमित होती है। अनेक दलों में नेतृत्व के चयन हेतु नियमित एवं पारदर्शी चुनावों की परंपरा का अभाव है। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक दल व्यक्तिनिष्ठ संस्थाओं में परिवर्तित हो जाते हैं और लोकतांत्रिक संगठनों के रूप में उनका विकास अवरुद्ध होता है। [Gupta \(2021\)](#)

इन समस्त चुनौतियों के कारण भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रभावशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यदि इन समस्याओं का समाधान पारदर्शिता, कठोर कानूनी प्रावधानों तथा व्यापक राजनीतिक सुधारों के माध्यम से किया जाए, तो भारतीय लोकतंत्र को अधिक सुदृढ एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

दलीय व्यवस्था में उभरती संभावनाएँ

भारतीय दलीय व्यवस्था वर्तमान समय में केवल विभिन्न चुनौतियों का सामना ही नहीं कर रही है, बल्कि इसके भीतर अनेक सकारात्मक संभावनाएँ भी उभरकर सामने आ रही हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं। सामाजिक जागरूकता में वृद्धि, तकनीकी प्रगति तथा नई पीढ़ी की सक्रिय राजनीतिक सहभागिता ने भारतीय राजनीति को नवीन स्वरूप प्रदान किया है। Verma (2020)

भारत विश्व के सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाले देशों में से एक है, जहाँ कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवा वर्ग से संबंधित है। हाल के वर्षों में युवाओं की राजनीतिक रुचि एवं सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अनेक युवा नेता स्थानीय निकायों से लेकर संसद तक सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। छात्र संगठनों, सामाजिक आंदोलनों तथा नवगठित राजनीतिक मंचों के माध्यम से युवाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप राजनीति में नवीन विचारधाराओं, नवाचार तथा ऊर्जावान दृष्टिकोण का समावेश हुआ है, जो पारंपरिक राजनीति की स्थिरता एवं जड़ता को चुनौती देने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने भारतीय राजनीति में व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब तथा व्हाट्सएप अब राजनीतिक प्रचार, जनसंपर्क एवं जनमत निर्माण के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। राजनीतिक दल डिजिटल अभियानों के माध्यम से सीधे जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक सूचनाओं का तीव्र प्रसार संभव हुआ है तथा जनभागीदारी में वृद्धि हुई है। डिजिटल मंचों ने राजनीतिक विमर्श को अधिक व्यापक, सुलभ और प्रभावशाली स्वरूप प्रदान किया है।

समकालीन भारतीय समाज में नागरिक राजनीतिक दलों एवं शासन संस्थाओं से अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही की अपेक्षा कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, मीडिया की सक्रिय भूमिका तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के दबाव ने शासन प्रणाली को अधिक खुला और उत्तरदायी बनाया है। चुनावी सुधारों की पहल, राजनीतिक वित्तपोषण की निगरानी तथा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों ने दलीय व्यवस्था में सुधार की संभावनाओं को सुदृढ़ किया है। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों पर स्वच्छ, नैतिक एवं पारदर्शी राजनीति अपनाने का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। दीर्घकाल तक सत्ता-केंद्रित राजनीति के प्रभुत्व के पश्चात अब कुछ राजनीतिक दल अपने मूल वैचारिक सिद्धांतों की ओर पुनः उन्मुख होने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे विचारों पर पुनः बल दिया जा रहा है। इससे राजनीति में वैचारिक स्पष्टता एवं वैचारिक प्रतिस्पर्धा के सुदृढ़ होने की संभावना है तथा नागरिकों को वैकल्पिक नीतिगत दृष्टिकोण उपलब्ध हो सकते हैं। Gupta (2021)

इन सभी उभरती संभावनाओं से यह स्पष्ट होता है कि यदि भारतीय दलीय व्यवस्था इन सकारात्मक परिवर्तनों को प्रभावी रूप से आत्मसात करे तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ बनाए, तो भारतीय लोकतंत्र का भविष्य अधिक स्थायित्वपूर्ण एवं उज्ज्वल सिद्ध हो सकता है।

परिणाम

भारतीय दलीय व्यवस्था ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्थायित्व एवं निरंतरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक वर्गों, क्षेत्रों तथा विचारधाराओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र अधिक समावेशी एवं प्रतिनिधिमूलक स्वरूप में विकसित हुआ है। क्षेत्रीय दलों के उदय ने संघीय ढाँचे को सुदृढ़ किया है तथा केंद्र की शक्तियों पर संतुलन स्थापित करने में सहायक भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सका है।

इसके अतिरिक्त राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण शासन संस्थाओं पर जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहने का दबाव निरंतर बढ़ा है। चुनावों के माध्यम से सत्ता परिवर्तन की संभावना ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को गतिशील एवं जीवंत बनाए रखा है, जिससे नागरिकों की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हुई है। तथापि, दलीय व्यवस्था से संबद्ध अनेक समस्याएँ लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती रही हैं। भ्रष्टाचार, अवसरवादी राजनीति तथा सामाजिक पहचान पर आधारित चुनावी रणनीतियों ने कई अवसरों पर जनकल्याण को गौण बना दिया है। गठबंधन सरकारों ने जहाँ एक ओर शासन को अधिक समावेशी बनाया है, वहीं दूसरी ओर नीतिगत अस्थिरता तथा प्रशासनिक निर्णयों में विलंब जैसी समस्याओं को भी जन्म दिया है। इस प्रकार से भारतीय दलीय व्यवस्था ने लोकतंत्र को व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया है, किंतु इसकी प्रभावशीलता एवं विश्वसनीयता राजनीतिक सुधारों, पारदर्शिता तथा नैतिक एवं उत्तरदायी नेतृत्व पर निर्भर करती है। यदि राजनीतिक दल जनकल्याण को प्राथमिक लक्ष्य बनाते हुए आंतरिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करें, तो यह व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत, स्थिर तथा प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलीय प्रणाली समय के साथ एक सुदृढ़, गतिशील एवं बहुआयामी राजनीतिक संरचना के रूप में विकसित हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात एकदलीय प्रभुत्व की अवस्था से लेकर वर्तमान बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप तक की विकास यात्रा ने भारतीय राजनीति को अधिक समावेशी तथा प्रतिनिधिमूलक बनाया है। विभिन्न सामाजिक समूहों, क्षेत्रों एवं विचारधाराओं को राजनीतिक मंच उपलब्ध होने से लोकतांत्रिक सहभागिता का व्यापक विस्तार संभव हुआ है तथा सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण पर प्रभावी संतुलन स्थापित किया गया है। तथापि, दलीय व्यवस्था अनेक गंभीर चुनौतियों से भी घिरी हुई है। भ्रष्टाचार, दल-बदल की प्रवृत्ति, जाति एवं धर्म आधारित राजनीति तथा राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के अभाव ने लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया है। इन समस्याओं के परिणामस्वरूप कई अवसरों पर शासन प्रणाली की विश्वसनीयता एवं कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इन चुनौतियों के प्रभावी समाधान हेतु व्यापक एवं संरचनात्मक राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता प्रतीत होती है। इनमें पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की स्थापना, कठोर कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन तथा राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। इसके साथ ही नागरिकों की बढ़ती जागरूकता एवं सक्रिय राजनीतिक सहभागिता भी लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

अंततः यदि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के साधन मात्र न रहकर जनकल्याण, सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक के रूप में कार्य करें, तो भारतीय लोकतंत्र अधिक स्थायित्वपूर्ण, उत्तरदायी तथा प्रभावशाली स्वरूप में विकसित हो सकता है।

संदर्भ सूची

- Gupta, V. K. (2021). Contemporary Indian Politics (समकालीन भारतीय राजनीति. दिल्ली). 188–193. Prabhat Prakashan.
- Gupta, V. K. (2021). Democracy and the Information Revolution (लोकतंत्र और सूचना क्रांति. दिल्ली). 85–90. Prabhat Prakashan.
- Mishra, S. C. (2017). The Evolution of the Indian Party System (भारतीय दलीय प्रणाली का विकास. इलाहाबाद). 34–40. Sahitya Bhavan.
- Mishra, S. C. (2017). The Indian Party System (भारतीय दलीय प्रणाली. इलाहाबाद). 54–58. Sahitya Bhavan.
- Mishra, S. C. (2017). The Indian Party System (भारतीय दलीय प्रणाली. इलाहाबाद). 110–114, 101–106. Sahitya Bhavan.
- Sharma, R. (2018). The Indian Political System (भारतीय राजनीतिक व्यवस्था. नई दिल्ली). 63–67. Rajkamal Prakashan.
- Sharma, R. (2018). The Indian Political System (भारतीय राजनीतिक व्यवस्था. नई दिल्ली). 92–96. Rajkamal Prakashan.
- Singh, R. (2019). A History of Modern Indian Politics (आधुनिक भारतीय राजनीति का इतिहास. पटना). 121–126. Bharati Bhavan.
- Singh, R. (2019). Indian Party System and Reform (भारतीय दलीय व्यवस्था और सुधार. पटना). 132–137. Bharati Bhavan.
- Verma, A. K. (2020). Challenges to Democracy in India (भारत में लोकतंत्र की चुनौतियाँ). 145–150. Orient Blackswan.
- Verma, A. K. (2020). Contemporary Indian Politics (समकालीन भारतीय राजनीति. दिल्ली). 172–177. Orient Blackswan.
- Verma, A. K. (2020). Democracy and Politics in India (भारत में लोकतंत्र और राजनीति. दिल्ली). 98–103. Orient Blackswan.